(b) The current average pit head prices of coal produced by CIL and SCCL are Rs. 382 and Rs. 452 per tonne respectively. These prices are exclusive of excise, royalty, sales tax, cess, taxes and other levies, if any, levied by Government, local authorities or other bodies.

(c) The company-wise position of cumulative Profits( )/Losses(as on 31st March, 1993 were as under :—

Companies	Cumulative Profits (+)Losses(—) (after tax provision and investment allowance reserve) (Rs. in crores)	
ECL	(—)	821.37
BCCL	(—)	1,159.96
CCL	(+)	30.39
WCL	(—)	194.30
NCL	(+)	221.50
SECL	(—)	28.17
MCL	(+)	43.73
CMPDIL	(+)	13.32
NEC/DCC/CIL	(—)	199.66
TOTAL CIL	(—)	2094.52
SCCL	(—)	772.94

Non-supply of coal by Mahanadi Coal fields Ltd.

1863. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1000 small scale industries in Orissa are suffering mostly due to the non-supply of coal by Mahanadi Coalfields Limited and as such their production is going low : and

(b) if so, what are the details in this regard and steps Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) No, Sir. According to information furnished by Coal India Limited, despatches of coal from Mahanadi Coalfields Ltd., to other industries in Orissa, which include SSI Industries has gone up during the current year by about 6% compared to the previous year. Almost all industrial units linked to Mahanadi Coalfields Ltd. are getting their full requirements of coal.

(b) Does not arise.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोयले की जरूरत

श्री वीरेन जे० शाह:

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कोयला मन्त्री 6 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 279 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कोयले की अनुमानतः कुल जरूरत 311 मिलियन मीटरी टन की रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में कोयले की इस जरूरत को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 19,374.07 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस मद पर व्यय हेतु अब तक केवल 12,357 करोड़ रुपये की धनराशि का आवेटन किया है ; और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या कोयले के उत्पादन के लिये जनवरी, 1994 तक निजी क्षेत्र से कुछ प्रस्ताव भी मिले हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव हैं, उनके माध्यम से लगभग कितना उत्पादन होने का अनुमान है और सरकार ने कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। किन्तु कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र दोनों ही के लिए आठवीं योजनावधि में योजना आयोग ने 1991-92 की कीमतों पर 12,357 करोड़ रु० का नियतन दर्शाया है। ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

करोड़ रुपये में

कम्पनी	(1991-92 की कीमतों पर)
कोल इंडिया लि०	8520
सिं०को०कं० लि० (आन्ध्र प्रदेश सरकार की इक्विटी सहित)	1050
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय अन्वेषण तथा पर्यावरण धंसाव नियन्त्रण	187
ने०लि०का०	
(क) खनन	800
(ख) विद्युत	1000
	12357

इस प्रकार आठवीं योजना अवधि में केवल कोयला क्षेत्र के लिये आवंटन 10557 करोड़ रु० की राशि का किया गया है।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा अन्तिम प्रयोग के लिये लौह एवं इस्पात के निर्माण में कार्यरत कम्पनियों से ग्रहीत कोयला खनन विकासार्थ अनुरोधों पर कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एक जांच समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसमें विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, राज्य सरकारों, कोल इण्डिया लिमिटेड, कोयला कम्पनियों आदि के सदस्य शामिल होते हैं।

विद्युत क्षेत्र के संबंध में ग्रहीत ब्लाकों का पता लगाने के लिये 15 विद्युत उत्पादन कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन विद्युत उत्पादन कम्पनियों में से 10 के ग्रहीत ब्लाकों का पता लगा लिया गया है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में 10 कम्पनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से तीन कम्पनियों के लिये ग्रहीत ब्लाकों का पता लगा लिया गया है। ये कम्पनियां सर्वेक्षण, खान आयोजन तथा खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए अन्य औपचारिकताएं आरम्भ करेंगे।

Augmenting output of coal during the Eighth Five Year Plan

1865. SHRI SOM PAL :

SHRI RAM NARESH YADAV :

Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether Government are planning to augment the output of coal ;

(b) if so, what are the yearwise targets for the Eighth five Year Plan period ;

(c) what measures are being adopted to achieve these targets ;

(d) what action is being taken to streamline the coal transport and delivery system : and

(e) what are the details thereof and the response thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) Yes, Sir.